छत्तीसगढ़ राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र

त्रैमासिक समाचार पत्रिका

अंक 5 (अप्रैल - जून 2018)

ईमेलः **chhattisgarh.sccc@gmail.com** वेबसाइट : **www.cgclimatechange.com**

मुख्य सम्पादक की कलम से.....

सम्माननीय पाठक,

राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र द्वारा त्रैमासिक समाचार पत्रिका का यह नया संस्करण प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है। प्रस्तुत संस्करण में जलवायु परिवर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों और तथ्यों का समावेश किया गया है। इसके अंतर्गत वानिकी से संबंधित तथा प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन/संरक्षण से संबंधित पारंपरिक स्वदेशी ज्ञान के महत्व पर विशेष प्रकाश डाला गया है, जो जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणाम जैसी गंभीर समस्या से निपटने हेतु एक महत्वपूर्ण उपकरण सिद्ध होगा।

राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान परिसर, रायपुर में स्थित छत्तीसगढ़ राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र, जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों निपटने हेतु अनवरत प्रयत्नशील है। त्रैमासिक पत्रिका के इस अंक में जैव विविधता के संरक्षण तथा सतत् समावेशी विकास लक्ष्य (Sustainable Development Goals) के संबंधित मुद्दों को केंद्रित/ लक्षित करते हुए जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में टिकाऊ कृषि के महत्व, उल्लेखित है। साथ ही केन्द्र द्वारा विभिन्न आयोजनों पर लिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी दी गई है।

सभी सम्माननीय पाठकों की रुचि को ध्यान में रखते हुए यह संस्था अपने आगामी अंको में आप सभी के सुझावों का हार्दिक स्वागत करती हैं। साथ ही यह भी अनुरोध हैं कि वह अपने द्वारा लिखे गए आलेखों को आगामी अंक में प्रकाशित करने हेतु सकारात्मक योगदान दें। इस पत्रिका के माध्यम से हम समाज के सभी वर्गो को उत्साहपूर्वक इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए भी आमंत्रित करते हैं।

Shirish

(शिरीष चन्द्र अग्रवाल)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक
राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान एवं नोडल अधिकारी
छत्तीसगढ़ राज्य जलवायु परिवर्तन केन्द्र, रायपुर

विषय-वस्तु

- जलवायु परिवर्तन गंभीरतम चुनौती सबको मिलजुलकर सामना करना होगा – श्री महेश गागड़ा, माननीय वनमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन
- एक्शन ऑन क्लाइमेट टुडे के द्वारा योजना के क्रियान्वयन हेतु सहमति
- **Climate Adaptation in Wetlands along the Mahanadi River Catchment area in Chhattisgarh** परियोजनांतर्गत विषय पर सहमति
- जलवायु परिवर्तन हेतु राष्ट्रीय अनुकूलन कोष के अंतर्गत स्वीकृत परियोजना हेतु माईक्रो प्लान
- छत्तीसगढ़ प्रमाणीकरण समिति (**CGCERT**) द्वारा जैविक उत्पादों का संकलन
- छत्तीसगढ राज्य जलवायु परिवर्तन केन्द्र द्वारा तापमान संबंधी अध्ययन
- जैव विविधता के संरक्षण एवं संवधन में पक्षियों के महत्व हेतु कृत्रिम घोसलाः– जैविक दबाव से प्रभावित पक्षी प्रजातियों के लिए वैकल्पिक आवास का क्रियान्वयन
- **S.F.R.I.** जबलपुर में क्षेत्रीय सह सुविधा केन्द्र कार्यशाला में **S.F.R.T.I.** छत्तीसगढ़ द्वारा प्रतिनिधित्व
- भयावह रूप ले रहा है जलवायु परिवर्तन, छत्तीसगढ़ के दो जिलों के साथ ही देश में कई इलाकों में गंभीर स्थिति बनने की चेतावनी
- औषधीय पौधों पर आधारित पारंपरिक स्वास्थ्य पद्धति के प्रचार प्रसार हेतु चलित परंपरागत स्वास्थ्य उपचार कैंप का आयोजन
- ''द क्लाइमेट ग्रुप'',नई दिल्ली द्वारा संबधित योजना की सैद्धान्तिक स्वीकृति
- औषधीय पौधों के पारंपरिक वैद्यों के ज्ञान के प्रमाणीकरण की पहल
- छत्तीसगढ़ प्रमाणीकरण समिति द्वारा जैविक प्रमाणीकरण पर प्रशिक्षण सम्पन्न
- विश्व पर्यावरण दिवस 2018
- विकास कार्यों में बैंकों की सहभागिता संबंधी नाबार्ड की बैठक में जलवायु परिवर्तन विषय पर सैद्धान्तिक सहमति
- जिला स्तरीय जलवायु परिवर्तन प्रकोष्ठ की बैठक दिनांक 12/06/2018 –बलौदाबाजार वनमण्डल
- जलवायु परिवर्तन संबंधित क्षेत्र भ्रमण एवं कार्यशाला
- समाचार शीर्षक
- **Abbreviation :**

a. NAFCC : National Adoption Fund on Climate Change

b. OCP : Open Cast Project

जलवायु परिवर्तन गंभीरतम चुनौती सबको मिलजुल कर सामना करना होगा - श्री महेश गागड़ा

जलवायु परिवर्तन वर्तमान में संपूर्ण विश्व के सामने गंभीरतम चुनौती के रूप में स्थापित है। इससे निपटने के लिये सभी को मिलकर प्रयास करना होगा, यह वक्तव्य श्री महेश गागड़ा मंत्री वन, विधि एवं विधायी कार्य छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दिनॉक 24—25 जून 2018 को पटना, बिहार में आयोजित ईस्ट इंडिया कान्क्लेव में रखे।

उल्लेखनीय है कि ईस्ट इंडिया कान्क्लेव का आयोजन, पर्यावरण एवं वनविभाग बिहार शासन द्वारा दिनॉक 24—25 जून 2018 को बिहार की राजधानी पटना में किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन डॉ. हर्षवर्धन, मंत्री, पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन, भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में श्री नीतिश कुमार, मुख्यमंत्री बिहार शासन उपस्थित हुये तथा इस अवसर में बिहार के उपमुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी तथा श्री महेश गागड़ा, मंत्री वन, विधि एवं विधायी कार्य छत्तीसगढ़ शासन शामिल हुये।

अपने वक्तव्य में माननीय वनमंत्री श्री गागड़ा द्वारा छत्तीसगढ़ में आदिवासी एवं सीमांत किसानों की ज्यादा संख्या होने और वर्षा आधरित जीवकोपार्जन के कारण जलवायु परिवर्तन के प्रति अत्याधिक संवेदनशील होने की जानकारी के साथ साथ छत्तीसगढ़ राज्य जलवायु परिवर्तन केन्द्र के द्वारा जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में किये जा रहे प्रयासों की जानकारी दी गई एवं बताया कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जलवायु परिवर्तन के हानिकारक परिणामों से निपटने के लिये संबंधित विभागों के लिए विस्तृत कार्ययोजना का निर्माण किया गया है, साथ ही जलवायु परिवर्तन केन्द्र द्वारा उक्त कार्ययोजना का संचालन सुनिश्चित किया जा रहा है ।

छत्तीसगढ़ राज्य पेरिस समझौते में निर्धारित किये गये भारत के राष्ट्रीय योगदान के प्रति पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है एवं राज्य में इस दिशा में लगातार प्रयास किये जा रहे है। साथ ही श्री गागड़ा जी द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा अंर्तराष्ट्रीय स्तर पर तापमान वृद्धि को रोकने हेतु गठित स्वैच्छिक संगठन Under 2 Coalition में देश में तेलंगाना के उपरांत द्वितीय राज्य के रूप में शामिल होने की जानकारी दी गई।

इस अवसर पर माननीय वनमंत्री श्री गागड़ा द्वारा जलवायु परिवर्तन की चुनौती को सामूहिक रूप से सामना करने का सुझाव देते हुये समस्त संबंधित विभागों को आपसी तालमेल स्थापित कर समेकित रूप से प्रयासों को गति देने का आह्वान किया गया ।

एक्शन ऑन क्लाइमेट टुडे के प्रतिनिधियों की नोडल अधिकारी से मुलाकात

डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट (डी. एफ. आई. डी.) द्वारा वित्त पोषित संस्था ''एक्शन ऑन क्लाइमेट टुडे (एक्ट)'' के प्रतिनिधियों द्वारा दिनांक 11/04/2018 को श्री शिरीष चंद्र अग्रवाल, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, छत्तीसगढ़ राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र से मुलाकात की गई। बैठक में एक्ट के छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा कार्यक्रम में टीम लीडर श्री सौमिक विश्वास एवं छत्तीसगढ़ की तकनीकी विशेषज्ञ श्रीमती आशा वर्मा उपस्थित रही।

बैठक में प्रतिनिधियों द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में एक्ट द्वारा संचालित गतिविधियों की जानकारी दी गई तथा संस्था द्वारा वर्ष 2018—19 के दौरान छत्तीसगढ़ में किए जाने हेतु प्रस्तावित कार्यों की जानकारी दी गई एवं उनके क्रियान्वयन हेतु राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र से सहयोग की अपेक्षा की गई। इस मौके पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, छत्तीसगढ़ राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र द्वारा उपस्थित प्रतिनिधियों को केंद्र द्वारा यथासंभव सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया गया। साथ ही छत्तीसगढ़ की लोक परंपराओं पर आधारित जलवायु परिवर्तन प्रयासों के दस्तावेजीकरण एवं उनकी सुदृढ़ीकरण हेतु स्थानीय जन समुदाय तथा विभागीय अमले के क्षमता विकास हेतु कार्यक्रम शामिल करने का सुझाव दिया गया।

भयावह रूप ले रहा है जलवायु परिवर्तन, छत्तीसगढ़ के दो जिलों के साथ ही देश में कई इलाकों में गंभीर स्थिति बनने की चेतावनी

विश्व बैंक की ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि 2050 तक 60 करोड लोग इससे गंभीर रूप से प्रभावित हो सकते है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव अलग—अलग स्थानों पर अलग है, लेकिन भारत समेत समूचे दक्षिण एशिया में कई ऐसे हॉट स्पॉट बन रहा है, जहां इसका दुष्प्रभाव ज्यादा होगा। इसलिए इन क्षेत्रों में रहने वाले लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होगें। रिपोर्ट के अनुसार, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के कारण भारत में दो बड़े बदलाव सामने आ रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के कारण भारत में दो बड़े बदलाव सामने आ रहे हैं। एक तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, दूसरे मानसून का पैटर्न बदल रहा है, ये दोनो बदलाव अर्थव्यवस्था के लिए घातक साबित हो सकता हैं। इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है, जो देश की जीडीपी की कुल 2.8 के बराबर होगी ।

देश में एक हजार से ज्यादा हॉटस्पॉट है, जो जलवायु परिवर्तन के खतरे से प्रभावित है। इससे सर्वाधिक प्रभावित दस जिलों मे सात जिले महाराष्ट्र के विदर्भ के है जबकि तीन जिले छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के है।

छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव और दुर्ग जिले हॉटस्पॉट प्रभावित जिलों में शामिल है, जिन दस राज्यों पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा उनमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, झारखण्ड , पंजाब, चंडीगढ़, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान तथा छत्तीसगढ़ शामिल है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक प्रभावित होने की आशंका व्यक्त की गई है। जलवायु परिवर्तन के हॉटस्पॉट महानगरों में चेन्नई, कोलकाता और मुंबई पर सबसे ज्यादा खतरे की बात कही गई है।

source:https://lalluram.com/climate-change-2-districts-of-chhattisgarh-warns-of-severe-situation-in-many-areas-in-the-country/

छत्तीसगढ राज्य जलवायु परिवर्तन केन्द्र द्वारा तापमान संबंधी अध्ययन

संस्थान परिसर से 5 कि.मी. की दूरी पर तापमान संबंधी आंकड़े एकत्रित करते हुए

छत्तीसगढ राज्य जलवायु परिवर्तन केन्द्र द्वारा रायपुर शहर के विभिन्न स्थानों पर तापमान मापी स्थापित कर तापमान एवं आर्द्रता संबंधी अध्ययन किया जा रहा है । इस अध्ययन का प्रमुख्य उद्देश्य राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर परिसर एवं शहर के विभिन्न स्थानों के तापमान एवं आर्द्रता संबंधी आंकडें एकत्रित कर उनका तुलनात्मक अध्ययन करना है, जिससे कि संस्थान परिसर में स्थित वृक्षारोपण की तापमान नियंत्रण में भागीदारी को वैज्ञानिक ढंग से निरूपित किया जा सकें। साथ ही इस अध्ययन के माध्यम से राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर परिसर को जलवायु स्मार्ट परिसर के रूप में स्थापित किये जाने हेतु मापदण्ड तैयार किये जावेगें ।

अध्ययन के शुरूआती चरण में राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर परिसर से 4—5 कि.मी. की परिधि में 04 अध्ययन प्रक्षेत्र चिन्हांकित कर तापमान एवं आर्द्रता संबंधी आंकडें लिए गये है जिनमें एवं शहर के अन्य स्थानों के तापमान में लगभग 1—3 डिग्री सेल्सियस तथा आर्द्रता में लगभग 5 से 10 प्रतिशत का अंतर पाया गया है। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक तापमान को नियंत्रित किए जाने के प्रयासों को गति देने के लिए गठित स्वैच्छिक संगठन Under2Coalition में छत्तीसगढ़ राज्य की तरफ से प्रतिनिधित्व किया जा रहा है। उक्त संगठन का उद्देश्य वर्ष 2050 तक वैश्विक तापमान को 2° सेल्सियस तक कम करने हेतु प्रयासों को बढ़ावा देना है। प्रस्तुत अध्ययन से स्पष्ट होता है कि मानव निर्मित वनों के माध्यम से तापमान में 1—3° सेल्सियस तक नियंत्रण किया जा सकता है।

संस्थान परिसर में तापमान संबंधी आंकड़े एकत्रित करते हुए

तापमान एवं आर्द्रता आंकड़ों की तुलनात्मक स्थिति

क्र	मापदण्ड	राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर परिसर के अंदर में	राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर परिसर के बाहर में	औसत तापमान एवं आर्द्रता में अंतर
1	औसत तापमान (°C)	32.6	35.4	2.8
2	औसत आर्द्रता (%)	57.0	52.1	4.9

Climate Adaptation in Wetlands along the Mahanadi River Catchment area in Chhattisgarh परियोजनांतर्गत आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण

दिनांक 13/04/2018 को राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र, राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित परियोजना "Climate Adaptation in Wetlands along the Mahanadi River Catchment area in Chhattisgarh" के सुचारु क्रियान्वयन हेतु बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में निम्नानुसार पदाधिकारीगण/ सदस्य उपस्थित हुए :—

श्री शिरीष चंद्र अग्रवाल, प्रधान मुख्य वन संरक्षक तथा नोडल अधिकारी, राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र, रायपुर, श्री ए. बी. मिंज, अपर निदेशक, राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर, श्री आलोक तिवारी, वनमण्डलाधिकारी, महासमुंद वनमण्डल, श्री अमिताभ बाजपेयी, वनमण्डलाधिकारी, धमतरी वनमण्डल, श्री विश्वेश कुमार, वनमण्डलाधिकारी, कसडोल बलौदाबाजार वनमण्डल, श्री एम. गोयल, डी. जी. एम., नाबार्ड, रायपुर, श्री अमित शर्मा, कन्सल्टेंट, नाबार्ड, रायपुर, डॉ. अनिल कुमार श्रीवास्तव, रिसर्च एसोसिएट, एवं स्टाफ जलवायु परिवर्तन (अनुकूलन), राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र, रायपुर

प्रधान मुख्य वन संरक्षक तथा नोडल अधिकारी, राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र द्वारा परियोजना क्रियान्वयन के संबंध में निम्नानुसार निर्देश दिए गए :—

- परियोजनांतर्गत किए गए बेसलाइन सर्वेक्षण प्रतिवेदन संबंधित वनमण्डलों को वनमण्डलाधिकारियों के अवलोकन एवं इनपुट्स हेतु बैठक में उपलब्ध कराया गया है। तदुपरांत वनमण्डलाधिकारी अपने कमेंट से दिनांक 30/04/2018 तक इस कार्यालय को सूचित करेंगे।
- परियोजनांतर्गत वन समितियां मानचित्रों के निर्माण हेतु सी. जी. कॉस्ट के साथ—साथ एफ. एम. आई. एस. वनमण्डल से भी संपर्क स्थापित किया जावे।
- परियोजनांतर्गत किए गए कार्यों को शुरु करने के पूर्व उनका जियोरिफरेंस इस कार्यालय को भेजा जाना सुनिश्चित करें, ताकि वन संसाधन मानचित्रों का निर्माण कराया जा सके।
- परियोजनांतर्गत किए जाने वाले कार्यों के पूर्व एवं पश्चात् के फोटोग्राफ्स आवश्यक रुप से तैयार किए जाएं।
- परियोजनांतर्गत किए गए कार्यों की प्रगति राज्य कार्यालय को उपलब्ध कराए जाने हेतु प्रारुप वनमण्डलों को उपलब्ध कराया जावे। वनमण्डलों द्वारा निर्धारित प्रारुप में मासिक प्रगति राज्य कार्यालय को भेजा जाना सुनिश्चित किया जाए।
- परियोजनांतर्गत हैल्थ कंपोनेंट में वनमण्डल स्तर पर आयुर्वेदिक चिकित्सकों/ परंपरागत चिकित्सकों के सहयोग से हैल्थ कैंप कराया जाए।

जलवायु परिवर्तन हेतु राष्ट्रीय अनुकूलन कोष के अंतर्गत स्वीकृत परियोजना हेतु माईक्रो प्लान

जलवायु परिवर्तन हेतु राष्ट्रीय अनुकूलन कोष अंतर्गत स्वीकृत परियोजना **Climate Adaptation in Wetlands along the Mahanadi River Catchment area in Chhattisgarh** परियोजनांतर्गत संबंधित वनमण्डलों के प्रस्तावित कार्यों क्रियान्वयन हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक के निर्देशानुसार, वनमण्डलाधिकारियों के मार्गदर्शन में वनमण्डल धमतरी, महासमुंद एवं बलौदाबाजार वनमण्डल अंतर्गत आने वाले परियोजना क्षेत्र का दिनांक 17/04/2018 से 30/04/2018 तक प्रवास हेतु भेजा गया था। उक्त प्रवास के दौरान वनमण्डलों द्वारा जलवायु अनुकूल रणनीति अंतर्गत मृदा एवं जल संग्रहण प्रस्तावित कार्यों का स्थल निरीक्षण, फोटोग्राफ्स, तथा ग्रामीणों के साथ जलवायु परिवर्तन के संबंध में बैठक लिया गया। बैठक में जलवायु परिवर्तन एवं प्रस्तावित कार्यों के संबंध में उनसे विस्तृत चर्चा किया गया। प्रवास कार्य उपरांत तीनों वनमण्डलों द्वारा पूर्व में प्राप्त परियोजना क्षेत्र के उपचार हेतु, मृदा एवं जल संग्रहण प्रस्तावित कार्यों के अनुरूप प्रत्येक वनमण्डल से एक वन कक्ष का चयन कर माईक्रो प्लान तैयार किया गया है। उक्त माईक्रो प्लान से परियोजना क्षेत्र में चयनित वन कक्ष में प्रस्तावित कार्य कराने में सुविधा होगी। वनमण्डल अंतर्गत चयनित वन कक्ष सारणी प्रस्तुत है ।

क्र.	वन कक्ष क्रमांक	वनमण्डल
1	244	धमतरी
2	178	महासमुंद
3	384	बलौदाबाजार

जैव विविधता के संरक्षण एवं संवर्धन में पक्षियों के महत्व हेतु कृत्रिम घोसला:- जैविक दबाव से प्रभावित पक्षी प्रजातियों के लिए वैकल्पिक आवास

वर्तमान में राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर द्वारा पक्षी प्रजातियों से संबधित तीन परियोजनाएं संचालित हैं। तीनों परियोजनाओं के अध्ययन क्षेत्र क्रमशः खुली खदानों (ओ.सी.पी.) जामपाली, छाल एवं बरौद, जिसमें मुख्य रुप से परियोजना का उद्देश्य कोयला खनन क्षेत्र में अवस्थित प्रभावित पक्षी प्रजातियों हेतु वैज्ञानिक पद्धति द्वारा वैकल्पिक आवास प्रदाय करना है। इस हेतु विगत माह 10/05/2018 को निदेशक, राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के इन अध्ययन क्षेत्रों में प्रवास के द्वौरान पाये गये पक्षी प्रजातियों के अनुरुप उनके वैकल्पिक आवास हेतु कृत्रिम घोंसला निर्माण पर कार्य प्रांरभ किया गया है । परियोजना क्षेत्रों में कृत्रिम घोसलों का निर्माण स्थानीय वन प्रबंधन समिति सदस्यों, ग्रामीणों द्वारा तैयार कर उन्हें रा.व.अ.एवं प्र.सं. के शोध दल के मार्गदर्शन में बनाया गया एवं घोसलों को स्थापित किया।

कृत्रिम घोंसला :—

कृत्रिम घोसला एक ऐसी संरचना है, जो पक्षी प्रजातियों के आवास का द्वितीय पूरक होता है। कृत्रिम घोसलों द्वारा पक्षियों के लिए आवास प्रदाय किया जाता है। इस संरचना का उपयोग उन पक्षी प्रजातियों के घोसले बनाने की प्रवृत्ति पर आधारित होता है। यह संरचना प्राकृतिक रुप से बने घोंसलों के समान ही कार्य करता है, जिसके द्वारा पक्षी प्रजाति प्रजनन पश्चात घोसलों में रहकर अण्डे सेते हैं एवं अपने परिवार सदस्यों के साथ जीवन काल व्यतीत करते हैं। कृत्रिम घोसले मुख्य रुप से हल्की लकडियों, सूखे घास, सूखे पत्ते, सूखी टहनियों, फसल अवशेष इत्यादि से बनाये जाते हैं। इन कृत्रिम घोसलों को तीन संरचानाओं में वर्गीकृत किया गया है। इन कृत्रिम घोसलों का पूर्ण विवरण निम्नानुसार है :—

अ. आदर्श घोसला डिजाइन 1 :—

विवरण: ये कृत्रिम घोसला हल्की लकड़ी से बना होता है। प्रायः ये कृत्रिम घोसला बक्से मौसम प्रतिरोधी काष्ठों जैसे साल, शीशम, बबूल इत्यादि लकड़ियों से बनाये जाते हैं। इसकी छत को ढलान आकार दिया जाता है जिससे बारिश एवं धूप से इस संरचना का बचाव होता है। यह कृत्रिम घोसला पीछे की ओर से खुला हुआ होता है, जिससे कि साफ सफाई एवं रख—रखाव का कार्य किया जाता है।

उपयुक्त प्रजातियां: गुहा/ खोखलों में घोसले बनाने वाले, शिकारी पक्षी, कबूतर, तोते, ओरिओल्स, पीले गौरैया, नीलकंठ इत्यादि।

ब. आदर्श घोसला डिजाइन 2 :—

विवरण: कूड़े, सूखे घास, सूखी टहनियां फसल अवशेष, छोटे उपज आदि से बना होता है। घोंसले छोटे घास के मैदानों के लिए उपयुक्त है और घास के मैदान के पक्षियों के लिए प्राकृतिक घोसला जैसा लगता है।

उपयुक्त प्रजातियां: घास के मैदान पक्षियों और कप घोसले पक्षियों आदि।

स. आदर्श घोसला डिजाइन 3 :—

विवरण: यह घोसला मुख्य रूप से जी आई तार के जालीनुमा ढांचे एवं शुष्क घास, छोटे उपज, सूखी टहनियां, सूखे फसल अवशेष आदि से बनाया जाता है।

उपयुक्त प्रजातियां: यह कृत्रिम घोसला साकर या प्लेटफार्म, लटकन घोसले, कुछ गोलाकार आकार के घोसले पक्षियों और स्थानीय रुप से पाए गए पक्षी और छोटे घास के पक्षी प्रजातियों आदि के लिए उपयुक्त है।

कृत्रिम घोसलों की संरचना का उपयोग बफर क्षेत्रों में पक्षी प्रजातियों के प्रजनन सफलता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इन कृत्रिम घोसलों को स्थापित किये जाने के साथ ही इनकी वैज्ञानिक पद्धति द्वारा अध्ययन किया जाना आवश्यक हैं, जिससे कृत्रिम घोसले को स्थापित करने, उनका नियमित निरीक्षण, रखरखाव एवं सम्पूर्ण कार्यान्वयन का मूल्यांकन इत्यादि पद्धति शामिल है।

छत्तीसगढ़ प्रमाणीकरण समिति (CGCERT) द्वारा जैविक उत्पादों का संकलन

दिनांक 05/05/2018 को श्री एस. सी. अग्रवाल, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर की अध्यक्षता में राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान परिसर में जैविक प्रमाणीकरण प्रक्रिया के तहत सीजीसर्ट में पंजीकृत किसानों द्वारा उगाए जा रहे जैविक उत्पादों जैसे कि अनाज, दलहन, तिलहन, वन्य शहद उत्पाद इत्यादि का नमूना प्रदर्शन हेतु रखा गया, जैविक उत्पादों के प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य जैविक प्रमाणीकृत उत्पादों के विक्रय को सुगम बनाने हेतु मार्केटिंग को दिशा प्रदान करना था। वर्तमान में छत्तीसगढ़ प्रमाणीकरण समिति (सीजीसर्ट) में कुल 1675 किसानों के जैविक प्रमाणीकरण का कार्य किया जा रहा है।

राज्य वन अनुसंधान सस्थान जबलपुर में क्षेत्रीय सह सुविधा केन्द्र कार्यशाला में राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान छत्तीसगढ़ द्वारा प्रतिनिधित्व

राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर में दिनांक 18/05/18 को क्षेत्रीय सह सुविधा केन्द्र, मध्य क्षेत्र, जबलपुर के कार्यशाला का लोकार्पण किया गया । उद्घाटन सत्र श्री राम प्रताप सिंह, अध्यक्ष, छ.ग. औषधि पादप बोर्ड एवं श्री रवि श्रीवास्तव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, म.प्र. की अध्यक्षता में सपन्न हुआ।

कार्यक्रम में उपस्थित राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं विभिन्न अधिकारियों सहित क्षेत्रीय निदेशक, क्षेत्रीय सह सुविधा केन्द्र एवं मुख्य अतिथि द्वारा उद्बोधन दिया गया, प्लेनरी सेसन में 04 मुख्य वक्ता 1. श्री श्रीवास्तव, अपर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, 2. श्री ए.के. द्विवेदी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वनौषधि पौधे एवं परंपरागत वानिकी ज्ञान तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग. राज्य वनौषधि पादप बोर्ड, रायपुर 3. श्री धर्मेन्द्र वर्मा, निदेशक, राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर, 4.श्री ए.बी. मिंज, अपर निदेशक, राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान में दिये जा रहे अनुसंधान कार्यो तथा जलवायु परिवर्तन विषयक परियोजनाओ की जानकारी दी गई। तकनीकी सत्र में औषधि पौधो के संरक्षण, संवर्धन, खेती, व्यापार एवं औषधि निर्माण से संबंधित विषयों के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा हुई, जिसमे वन विभाग, राज्य वनौषधि पादप बोर्ड, निजी औषधि पौधो के उत्पादक किसान, ट्रेडर्स, औषधि निर्माता एवं गैर सरकारी संगठन भाग लिये।

इसमे मुख्य रूप से उच्च मांग वाले औषधि पौधों का संरक्षण ,औषधि पौधों को सतत एवं अहानिकारक दोहन, औषधि पौधो की खेती,प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन, पैकेजिंग, भंडारण एवं मार्केटिंग पर विस्तृत चर्चा हुई। मध्य क्षेत्र, जबलपुर के क्षेत्रीय निर्देशक द्वारा बताया गया कि आगामी समय में औषधि पौधो के किसान, व्यापारी, वैद्यो एवं औषधि निर्माता के लिए क्षेत्रीय स्तर पर विशेष कार्यक्रम किया जायेगा।

औषधीय पौधों पर आधारित पारंपरिक स्वास्थ्य पद्धति के प्रचार प्रसार हेतु चलित परंपरागत स्वास्थ्य उपचार कैंप

छत्तीसगढ़ जलवायु परिवर्तन केन्द्र द्वारा NAFCC परियोजनांतर्गत पारंपरिक स्वास्थ्य पद्धति के प्रचार प्रसार हेतु संबंधित वनमण्डलों (धमतरी, महासंमुद एवं बलौदा बाजार) में चलित परंपरागत स्वास्थ्य उपचार कैंप का आयोजन कराया गया।

महासमुंद

दिनांक 23/05/2018 को पारंपरिक स्वास्थ्य पद्धति के प्रचार प्रसार के लिए वनमण्डल महासमुंद के सिरपुर वन परिक्षेत्र ग्राम अमलौर, केडियाडीह, कर्राडीह, मरौद, बोरिद, चुहरी तथा पासिद क्षेत्र में पहुंचकर बीट गार्ड, साहू जी तथा क्षेत्रीय वैद्यराज 1. श्री दउआराम निषाद, 2. श्री सोहन साहू, 3. श्री धनीराम, 4. श्री गोपाल सिदार, 5. श्री कमल नारायण, 6. श्री आनंद कुमार सिन्हा से मिलकर उपचार स्वास्थ्य कैंप हेतु कार्य योजना का प्रारुप बनाया गया तथा ग्रामवासियों को कोटवार के माध्यम से कैंप की जानकारी दी गई। दिनांक 24/05/2018 को प्रातः 8:30 बजे से उपचार स्वास्थ्य कैंप में वैद्यराज जी के माध्यम से स्वास्थ्य परामर्श दिया गया। कैम्प ग्राम 1. अमलौर/ केडियाडीह, 2. पासिद/ चुहरी/ कर्राडीह, बोरिद में दो स्थानों पर संपन्न कराया गया तथा ग्रामवासियों द्वारा इसका पूरा लाभ लिया गया।

बलौदाबाजार

दिनांक 25/05/2018 को प्रचार प्रसार हेतु वनमण्डल बलौदाबाजार के अर्जुनी वन परिक्षेत्र में ग्राम दलदली, महकोनी, खोसड़ा, लिमतरी, महुआडीह, करियाटार तथा सिंघीटार में पहुंचकर वैद्यराज 1. श्री कृपाराम विश्वकर्मा, 2. श्री चमार सिंह, 3. श्री कवल सिंह, 4. श्री भक्तूराम, 5. श्री रामाधार पैंकरा, 6. श्री केजूराम से मिलकर कैंप लगाने हेतु उचित स्थान का चयन कर कार्य योजना बनाई गई तथा ग्राम में कोटवार के माध्यम से कैम्प आयोजन हेतु ग्रामवासियों को अवगत कराया गया।दिनांक 26/05/2018 को प्रातः 8:30 बजे से 11:00 बजे तक ग्राम खोसड़ा में उपचार स्वास्थ्य कैंप लगाया गया। प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक दलदली में स्वास्थ्य कैंप लगाया गया तथा दोपहर 12:30 से 2:00 बजे तक ग्राम महकोनी में उपचार स्वास्थ्य परीक्षण के द्वारा वैद्यराज के माध्यम से परामर्श दिया गया तथा सभी वैद्यराज द्वारा सामूहिक परिचर्चा की गई।

धमतरी

पारंपरिक स्वास्थ्य पद्धति के प्रचार प्रसार हेतु दिनांक 21—22 मई 2018 को प्रवास हेतु रायपुर से दुगली निकले। वहां पहुंच कर कार्य योजना तथा वैद्यराज की सूची बनाकर कैंप हेतु सूचना समस्त ग्रामवासियों को कोटवार के माध्यम से दिनांक 21/05/2018 को दी गई। स्वास्थ्य कैंप का आयोजन दिनांक 22/05/2018 को प्रातः 8:30 बजे तीन स्थानों पर ग्राम मुनईकेरा, दिनकरपुर एवं भोभलाबहरा में संपन्न कराया गया, जिसमें प्रमुख रुप से कैंप दल के साथ वहां के वन क्षेत्रपाल, श्री संदीप कुमार सोम जी, सहायक वन परिक्षेत्राधिकारी, श्री मरकाम जी, वनरक्षक, श्री विरेन्द्र नेताम तथा उपचार कैंप में वहां के पारंपरिक पद्धति में दक्ष वैद्यराज 1. श्री दशरथ नेताम, 2. श्री खेमराज सेन, 3. श्री रामलाल कुंजाम, 4. श्री भगवान सिंह नेताम, 5. श्री देव सिंग मंडावी, 6. श्री रमेंश मरकाम, 7. श्री मिथलेश कुमार आदि उपस्थित थे। पारंपरिक उपचार स्वास्थ्य कैंप का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। उपरोक्त पारंपरिक उपचार स्वास्थ्य कैंप को सफलतापूर्वक संपन्न कराया गया।

द क्लाइमेट ग्रुप द्वारा केंद्र को तकनीकी स्वीकृति की पेशकश

द क्लाइमेट ग्रुप, नई दिल्ली कार्यालय के प्रतिनिधि सुश्री नेहमत कौर, वरिष्ठ प्रबंधक एवं सुश्री शिल्पी सामंतराय, परियोजना अधिकारी द्वारा दिनांक 23/05/2018 को श्री शिरीष चंद्र अग्रवाल, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, छत्तीसगढ़ राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र से मुलाकात की गई। मुलाकात में सुश्री सामंतराय द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के अंडर2कोयलेशन में सदस्य होने के नाते द क्लाइमेट ग्रुप द्वारा संचालित परियोजनाओं में राज्य को प्राथमिकता दिए जाने की जानकारी दी गई। साथ ही द क्लाइमेट ग्रुप द्वारा समय–समय पर विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए नोडल अधिकारी महोदय को आमंत्रित किया गया। उल्लेखनीय है कि द क्लाइमेट ग्रुप जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में कार्यरत एक अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जो कि विशेषकर जलवायु परिवर्तन–शमन के क्षेत्र में विश्व के लगभग 62 देशों में कार्य कर रही है। संस्था के प्रतिनिधियों द्वारा केंद्र को जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग एवं मार्गदर्शन देने हेतु अपनी स्वीकृति प्रदान की गई।

औषधीय पौधों के पारंपरिक वैद्यों के ज्ञान के प्रमाणीकरण की पहल

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर द्वारा छत्तीसगढ़ प्रदेश में कार्यरत पारंपरिक सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए स्वैच्छिक प्रमाणन विषय पर भी बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश में कार्यरत पारंपरिक सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के ज्ञान एवं अभ्यासों को आयुष विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली के योजना अनुरुप प्रमाणीकरण के अंतर्गत जोड़ना था, ताकि इसे प्रमाणीकरण की धारा में लाकर इनके ज्ञान एवं अभ्यासों को मान्यता प्राप्त हो सके तथा प्रदेश में उपलब्ध औषधीय पौधों का विनाश विहीन विदोहन तरीके से समुचित उपयोग हो।

आयुष विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली को बजट एवं आवश्यक सहयोग हेतु प्रस्ताव दिनांक 29/05/2018 को भेजा गया है। इसके अतिरिक्त औषधीय पौधों के प्रमाणीकरण हेतु आयुष विभाग के योजनांतर्गत राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड एवं क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में तैयार किए गए प्रमाणीकरण योजना हेतु किए गए पहल से भी अवगत कराया गया तथा इस क्षेत्र में प्रमाणीकरण हेतु सीजीसर्ट द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बारे में बताया गया।

छत्तीसगढ़ प्रमाणीकरण समिति द्वारा जैविक प्रमाणीकरण पर प्रशिक्षण सम्पन्न

दिनांक 02/06/2018 को श्री एस. सी. अग्रवाल, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर की अध्यक्षता में राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान परिसर छत्तीसगढ़ जैविक प्रमाणीकरण समिति द्वारा कार्यालय के समस्त आर. ए., एस. आर. एफ., जे. आर. एफ., फील्ड एवं प्रोजेक्ट असिस्टेंट को जैविक प्रमाणीकरण पर प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य प्रमाणीकरण समिति के कार्यों को समझना तथा भविष्य में संबंधित कार्यों हेतु सहयोग को बढ़ाना था।

विश्व पर्यावरण दिवस 2018
भारत वैश्विक मेजबान के रूप में, थीम: बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन

अगर दुनिया में तेजी से फैलते प्रदूषण पर काबू नहीं किया, तो वह दिन दूर नहीं जब हमारा सांस लेना दूभर हो जाएगा। 05 जून को दुनियाभर में पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद है, दुनिया वालों पर्यावरण के लिए सुरक्षा और संरक्षण के प्रति जागरुक करना। वैसे इस दिन को दुनिया भर में मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1972 में की थी, लेकिन पहला विश्व पर्यावरण दिवस 05 जून 1974 को मनाया गया था और इस बार 45 वां विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत पर्यावरण की सुरक्षा और उसके संरक्षण के लिए किया गया था। विश्व पर्यावरण दिवस मनाने के पीछे यह उद्देश्य है कि लोगों को इस बारे में जागरुक किया जा सके कि आखिर क्यों पर्यावरण की सुरक्षा जरुरी है।

उल्लेखनीय है कि थाईलैंड प्लास्टिक बैग का दुनिया के सबसे बड़े उपभोक्ताओं में से एक है और हर साल देश में बड़ी संख्या में समुद्री जीव मारे जाते हैं। पर्यावरण पर लापरवाही का मामला यहीं नहीं खत्म होता है। भले ही आज भारत वर्ष 2018 का पर्यावरण दिवस को होस्ट कर रहा हो, लेकिन पूरा देश वायु प्रदूषण और पीने के पानी की कमी से जूझ रहा है और यह कहने में जरा भी शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए कि भले ही हम अच्छे होस्ट हों और अतिथि की उपमा देव से करते हों, लेकिन पर्यावरण देव की चिंता हमें नहीं हैं।

प्लास्टिक प्रदूषण तथ्य

- पूरा विश्व प्रत्येक वर्ष 5 खरब प्लास्टिक बैग्स इस्तेमाल करता हैं।
- प्रत्येक वर्ष 180 लाख टन प्लास्टिक समुद्र में डाले जाते हैं, जो कि हर मिनट में एक ट्रक कचरा समुद्र में डालने के बराबर है।
- पिछले दशक में हमने इतना प्लास्टिक बनाया है, जितना कि पिछले पूरे शताब्दी में नहीं बना।
- हम जितना प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं, उसका 50 प्रतिशत एकल उपयोग अथवा डिपोजेबल प्लास्टिक होता है।
- हम हर मिनट में 10 लाख प्लास्टिक बोतलें खरीदते हैं।
- हम जितना कूड़ा उत्पन्न करते है, उसका 10 प्रतिशत प्लास्टिक ही होता है।

प्लास्टिक को वैश्विक स्तर पर गंभीर खतरा माना गया है। इस दौरान डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि प्लास्टिक को वैश्विक स्तर पर गंभीर खतरा माना गया है। इसके मद्देनजर इस चुनौती से निपटने के लिए तथा प्लास्टिक के खतरे को खत्म करने के लिए यह शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस 2018 मात्र एक प्रतीकात्मक समारोह नहीं, बल्कि एक मिशन है।

source:https://www.amarujala.com

विकास कार्यों में बैंकों की सहभागिता संबंधी नाबार्ड की बैठक में जलवायु परिवर्तन विषय पर सैद्धान्तिक सहमति

दिनांक 06/06/2018 को नाबार्ड कार्यालय, रायपुर में अपरान्ह 2:30 बजे बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता श्री आर. अमालोरपवनाथन, डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर, नाबार्ड द्वारा की गई। बैठक में श्री अशोक बजाज, अध्यक्ष, अपेक्स बैंक, छत्तीसगढ़ पद्मश्री फूलवासन यादव पद्मश्री शमशाद बेगम, श्री अनूप श्रीवास्तव, सचिव, कृषि विभाग, छत्तीसगढ़ शासन श्री पाण्डेय, डिप्टी डायरेक्टर, उद्यानिकी विभाग, छत्तीसगढ़ शासन प्रमुख बैंकों के जोनल अधिकारी श्री ए. बी. मिंज, अपर निदेशक, छत्तीसगढ़ राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र, रायपुर, डॉ. अनिल कुमार श्रीवास्तव, रिसर्च एसोसिएट, छत्तीसगढ़ राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र, रायपुर नाबार्ड के स्थानीय अधिकारीगण शामिल हुए। बैठक का मुख्य उद्देश्य नाबार्ड द्वारा छत्तीसगढ़ में किए जा रहे विकास कार्यों को बढ़ावा देने हेतु बैंकों की सहभागिता में वृद्धि करना था। नाबार्ड द्वारा राज्य में किए जा रहे इस क्षेत्र के कार्यों की जानकारी दी गई। तदुपरांत श्री आर. अमालोरपवनाथन द्वारा उपस्थित बैंक प्रतिभागियों को निम्नानुसार निर्देश दिए गए :—

- बैंकों को अपने मूल उद्देश्य ग्रामीण विकास की प्राप्ति हेतु स्थानीय स्तर पर concentrated efforts लगाना चाहिए, जिससे कि स्पष्ट प्रभाव दृष्टिगोचर हो।
- बैंकों को अपने कार्य क्षेत्र में प्रति शाखा एक ग्राम को गोद लेकर विकास कार्यों हेतु राशि उपलब्ध कराया जावे।
- भूमिहीन परिवारों हेतु योजना का संचालन किया जाए।
- ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल ए.टी.एम., क्षमता विकास आदि कार्यों का प्रचार प्रसार किया जाए।
- राष्ट्रीय मिशनों के अनुरुप बैंकों में न्यूनतम अधोसंरचनाएं यथा टायलेट्स इत्यादि का निर्माण कराया जाए।
- बैंकों की सी. एस. आर. राशि को ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत अधोसंरचना विकास में उपयोग किया जाए।

जिला स्तरीय जलवायु परिवर्तन प्रकोष्ठ की बैठक दिनांक 12/06/2018 -बलौदाबाजार वनमण्डल

दिनांक 12/06/2018 को जिला बलौदाबाजार में जिला स्तरीय जलवायु परिवर्तन प्रकोष्ठ की बैठक का आयोजन श्री जे. पी. पाठक, कलेक्टर, बलौदाबाजार की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में जिला जलवायु परिवर्तन प्रकोष्ठ के 22 सदस्य एवं जिला स्तरीय विभिन्न विभागों के 48 पदाधिकारी कुल 70 सदस्य उपस्थित हुए। उक्त बैठक में राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र, रायपुर कार्यालय से डॉ. अनिल कुमार श्रीवास्तव, रिसर्च एसोसिएट एवं श्री राकेश कुमार श्रीवास, जे. आर. एफ. प्रतिनिधि के रुप में उपस्थित रहे।

बैठक का शुभारंभ कलेक्टर, बलौदाबाजार के संबोधन से हुआ, जिसमें उनके द्वारा उपस्थित सदस्यों को समन्वय के साथ जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में कार्य करने का आह्वान किया गया। तत्पश्चात् सदस्य सचिव, वनमण्डलाधिकारी द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत परियोजना "Climate adaptation in wetlands along the Mahanadi River Catchment area in Chhattisgarh" अंतर्गत वनमण्डल बलौदाबाजार में किए जा रहे कार्यों से उपस्थित सदस्यों को अवगत कराते हुए विभागीय स्तर पर चल रहे प्रयासों के संबंध में जानकारी दी। तदुपरांत बैठक में निम्नानुसार कार्यवाही की गई :—

- डॉ. अनिल कुमार श्रीवास्तव, रिसर्च एसोसिएट, राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र, रायपुर द्वारा राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र एवं जिला जलवायु परिवर्तन प्रकोष्ठ के उद्देश्य एवं कार्यविधि पर प्रस्तुतिकरण दिया गया। साथ ही उपरोक्त परियोजना के संबंध में प्रस्तुतिकरण दिया गया।
- डॉ. श्रीवास्तव द्वारा जलवायु परिवर्तन पर प्रस्तुतिकरण में केंद्र द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर प्रकाश डाला गया।
- जिला जलवायु परिवर्तन प्रकोष्ठ के बेहतर क्रियान्वयन हेतु कलेक्टर महोदय द्वारा डी. पी. आर. की मांग की गई, ताकि विभिन्न संबंधित विभागों को भेजा जा सके एवं विभागीय अधिकारी अपने दायित्व का निर्वहन कर सकें।
- अध्यक्ष महोदय ने परियोजना क्षेत्रों का समस्त संबंधित विभागों को लेकर सामूहिक क्षेत्र भ्रमण एवं कार्यशाला आयोजन कर क्षेत्र की मांग के अनुरुप कार्य योजना तैयार करने हेतु निर्देशित किया।
- अध्यक्ष महोदय द्वारा क्षेत्र में संचालित परियोजना के समयावधि पर चर्चा करते हुए विभागीय अधिकारियों से समन्वय हेतु निर्देशित किया।
- वनमण्डलाधिकारी महोदय द्वारा जिले के विकासखंड कसडोल, ग्राम महकोनी, दलदली, खोसड़ा एवं बिलाईगढ़ के अंतर्गत ग्राम लिमतरी, मोहाडीह, करियाटार एवं सिंगीटार में जो की परियोजना क्षेत्र हैं, उनमें जलग्रहण कार्यों के विषय पर जानकारी दी गई।
- बैठक उपरांत वनमण्डलाधिकारी, बलौदाबाजार वनमण्डल से हुई चर्चा में उपरोक्तानुसार कार्यशाला एवं क्षेत्र भ्रमण के आयोजन हेतु दिनांक 21/06/2018 के आसपास की तिथियों को निर्धारित किए जाने का सुझाव दिया गया।

जलवायु परिवर्तन संबंधित कार्यशाला सह क्षेत्र भ्रमण

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा स्वीकृत परियोजना Climate Adaptation in Wetlands along the Mahanadi River Catchment Area in Chhattisgarh अंतर्गत संबंधित विभागों हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान तथा नोडल अधिकारी, राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र के निर्देशानुसार दिनांक 22/06/2018 को वनमण्डल बलौदाबाजार के परियोजना क्षेत्र ग्राम महकोनी, अर्जुनी परिक्षेत्र, जनपद पंचायत कसडोल में एक दिवसीय कार्यशाला, परियोजना क्षेत्र अंतर्गत पदस्थ संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों, स्थानीय जन प्रतिनिधियों एवं संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के सदस्यों को सम्मिलित कर परियोजना क्षेत्र में क्षेत्र भ्रमण एवं कार्यशाला का आयोजन किया गया।

इस कार्यशाला में संबंधित विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे एवं कार्यशाला सह क्षेत्र भ्रमण कार्यक्रम के सफल संचालन एवं क्रियान्वयन में आवश्यक सहयोग प्रदान किया। कार्यशाला में उपस्थित विभिन्न शासकीय विभागों के प्रतिनिधियों द्वारा परियोजना के सुचारू संचालन हेतु अपने—अपने विभागों द्वारा विषय संबंधित प्रस्तावों के माध्यम से परियोजना क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा।

समाचार शीर्षक

पर्यावरण दिवस | लोगों में जागरूकता लाने कई सामाजिक संस्थाओं ने शहर में चलाया अभियान

पॉलीथिन का बहिष्कार, कपड़े की थैलियां और पौधे बांटे गोष्ठी भी रखी, इस तरह दिया हरियाली बचाने का संदेश

ज्यादातर मंगलवों की अपील-पॉलीथिन छोड़े

जलवायु कुल तंत्र के लक्ष्यों से संबंधित को मोबाइल रखी नर्सरी में ने पॉलीथिन बैगेज चलाया।

महापौर समेत 125 लोगों ने लिया 11 साल में हरियाली वापस लाने का संकल्प

बच्चों ने पेंटिंग से समझाया पेड़ों का महत्व वाहन प्रदूषण जांच शिविर भी लगाया गया

3 साल से लगा रहे हैं पौधे, बढ़ाएंगे टीम

पौधरोपण ताकि बचे लोटे गार्डन की ओर

एयरपोर्ट में चलाया जागरूकता अभियान

जवानों ने लगाए पौधे

पर्यावरण बचाने कपड़े की थैलियां बांटीं

जलवायु परिवर्तन संबंधित कार्यशाला सह क्षेत्र भ्रमण कार्यक्रम संपन्न

बलौदाबाजार (नवपदेश)

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्वीकृत एवं छत्तीसगढ़ राज्य जलवायु परिवर्तन केन्द्र द्वारा संचालित स्थानीय हितग्राहियों एवं विभागों हेतु वन ग्राम मालकोनी में आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला सह क्षेत्र भ्रमण कार्यक्रम सफलता पूर्वक सम्पन्न हुआ। उक्त प्रशिक्षण सह क्षेत्र भ्रमण कार्यक्रम में वन मण्डलाधिकारी, बलौदाबाजार विशेष कुमार, राज्य वन अनुसंधान संस्थान रायपुर के डॉ. अनिल श्रीवास्तव एवं उनके सहयोगी वन परिक्षेत्र अधिकारी अतुर्ली, टी. आर.वर्मा, वन परिक्षेत्र अधिकारी, बिलाईगढ़ जे.पी.जायसवाल, वन विभाग के अधिकारी, कर्मचारी एवं समस्त 22 विभागों के अधिकारी एवं ग्रामवासी, एलदली, खोसडा, लिमतरी, मौलाडीह, करियाटार एवं सिर्वीटार के ग्रामीण बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। इस अवसर पर वन मण्डलाधिकारी श्री कुमार ने जलवायु परिवर्तन परियोजना के महत्व को समझाते हुए समस्त 22 विभागों के अधिकारियों को अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने हेतु निर्देशित किया। अंतिम में भोजन पश्चात क्षेत्र भ्रमण किया गया एवं क्षेत्र की स्थानीयता के अनुरूप प्रोजेक्ट, एक सप्ताह के अंदर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। सभी ग्रामिणों द्वारा उक्त परियोजना स्वीकृत होने पर प्रसन्नता व्यक्त की गई है।

नवभारत 30/6/18

छत्तीसगढ़ को हॉटस्पॉट बनने से रोकने ठोस कदम जरूरी

तापमान में 2 डिग्री का बदलाव बनेगा भारी मुसीबत

एक्सपर्ट बोले, तमाशा मुद्दा उठा रहे पर एक्शन ही नहीं होती

प्रदेश का पारा बढ़ रहा है, बारिश का मात्रा घटती जा रही

■ नवभारत ब्यूरो, रायपुर.

बहुत कान करने की जरूरत : डॉ. परवेज

ये उपाय करने होंगे तुरंत

तापमान में ...

विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार को इस दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे. आम लोगों को भी पर्यावरण के प्रति जागरूक होना होगा. विश्व बैंक की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ शीर्ष हॉटस्पॉट होगा. जनजीवन पर इसका खासा असर दिखेगा. लोगों में स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बढ़ेंगी और राज्य की आर्थिक स्थिति भी कमजोर होगी. कृषि का उत्पादन घट जाएगा, जो अच्छे संकेत नहीं हैं.

रायपुर, शनिवार, 30 जून 2018

नवभारत

जलवायु परिवर्तन: देश को अब और खतरे में नहीं डाल सकते

पर्यावरण को लेकर हमें और भी परिपक्व नीति अपनानी पड़ेगी.

विश्व बैंक की ताजा रिपोर्ट में जो भयावह तस्वीर दिखाई गई है, उसे लेकर अब गंभीर हो जाने का वक्त आ गया है. जलवायु परिवर्तन का खतरा दिनोंदिन गंभीर होता जा रहा है तथा भारत सहित दक्षिण एशिया इसके दुष्प्रभाव के क्षेत्र में आ गए हैं. तापमान में वृद्धि तथा मानसून के पैटर्न में बदलाव के रूप में इसे छत्तीसगढ़ में नहीं पूरे देश में वर्षों से महसूस किया जा रहा है. यह बदलाव हमारी अर्थव्यवस्था सहित रहन-सहन के लिए घातक साबित हो सकता है. छत्तीसगढ़ सहित उत्तरप्रदेश, हरियाणा, झारखंड, पंजाब, आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान में जलवायु परिवर्तन का असर आने वाले वर्षों में निरंतर बढ़ते हो जाएगा. जलवायु परिवर्तन से निबटने के लिए अब और भी ज्यादा सक्रियता की जरूरत है, तो दुनिया उलटी दिशा में जा रही है. जलवायु परिवर्तन के लिहाज से देखा जाए तो बीते सालों ने सबसे बुरे रिकॉर्ड बनाए हैं. इस दौरान दुनिया को तबाह कर देने वाली कई घटनाएं आकार लेती दिखीं. हवा और समुद्र की सतह का जो औसत तापमान दर्ज हुआ है वह औद्योगिक क्रांति के सालों के बाद से सबसे ज्यादा था. वायुमंडल में सबसे ज्यादा कार्बन डाईआक्साइड भी दर्ज किया गया. आर्कटिक में बर्फ पिघलकर टूटने की घटनाएं सामने आई हैं. समुद्र के स्तर में बढ़ोतरी के साथ दुनिया में सबसे ज्यादा सूखे की मार भी पड़ी है. ये ऐसी हकीकतें हैं जो जलवायु परिवर्तन की अवधारणा के किसी भी विरोधी के लिए चिंता का सबब होनी चाहिए. इसलिए भी कि इनके नतीजे जलवायु परिवर्तन को मानने या न मानने वालों में भेद नहीं करेंगे. सर्वनाश की आहट देती एक आपदा हमारे सामने घट रही है लेकिन इसे खबरों और जनमानस में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, क्योंकि वहां राजनीतिक टकराव जैसी दूसरी वास्तविकताएं प्राथमिकता में हैं लेकिन आगे जो तूफान हम पर बरसने वाला है उसे अपनी मौजूदगी जताने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा. इस बात की संभावना है कि पर्यावरण पीड़ित शरणार्थियों का समूह उस ओर दौड़ेगा, जहां हालात थोड़े बेहतर होंगे. इस खतरनाक दौर में भी गंभीरता का अभाव बना हुआ है. विश्वस्तर पर संरक्षणवाद और आत्मकेन्द्रित नीतियां जलवायु परिवर्तन से जिम्मेदार देशों को मुंह मोड़ने के लिए विवश कर रही हैं. विडंबना है कि एमेजन से लेकर कांगो बेसिन तक हर मिनट 40 फुटबॉल मैदान के बराबर जंगल काटकर वीरान किए जा रहे हैं. भारत में भी शहरों के सौंदर्यीकरण के लिए लाखों वृक्षों की बलि देने के लिए तत्परता दिखाई जा रही है. कोई भी देश अपनी धरती को मनुष्यों के रहने लायक बनाने के लिए गतिशीलता दिखाने की जगह सिर्फ चिंता जताकर ही अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर रहे हैं. जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंता करने व इस दिशा में कुछ करने की सबसे ज्यादा जरूरत है. पर्यावरण को लेकर हमें और भी परिपक्व नीति अपनानी पड़ेगी. भारत में पड़ने वाले दुष्प्रभाव को लेकर तात्कालिक और दीर्घकालीन नीतियां बनाने से लेकर अमल में चुस्ती दिखाने की आवश्यकता है.

सम्पादक मंडल

- शिरीष चन्द्र अग्रवाल (मुख्य सम्पादक)
- डॉ. राजेश गुप्ता
- डॉ. अनिल कुमार श्रीवास्तव
- श्री ए. बी. मिंज
- श्री मानस उज्जैनी
- नेहा श्रीवास

छत्तीसगढ़ राज्य जलवायु परिवर्तन केन्द्र
राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान परिसर
विधानसभा के पास, बलौदा बाजार रोड, जीरो प्वाइंट
रायपुर – 493111, छत्तीसगढ़
ईमेल: chhattisgarh.sccc@gmail.com
वेबसाइट : www.cgclimatechange.com